



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2614]	नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 22, 2014/पौष 1, 1936
No. 2614]	NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 22, 2014/PAUSHA 1, 1936

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3251(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार यह निर्धारित करने के लिए कि क्या असम के यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसोम (उल्फा) को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण विद्यमान हैं अथवा नहीं, एतद्वारा, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सुश्री इन्दरमीत कौर की अध्यक्षता में एक “विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण” का गठन करती है।

[फा. सं. 11011/28/2014-एनई-V]

शम्भू सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2014

S.O. 3251(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes “The Unlawful Activities (Prevention) Tribunal” consisting of Ms. Indermeet Kaur, Judge of Delhi High Court, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient causes of declaring the United Liberation Front of Asom (ULFA) of Assam as Unlawful Association.

[F. No. 11011/28/2014-NE-V]

SHAMBHU SINGH, Jt. Secy.